Spinning Mills in Punjab

1919. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the number of spinning mills set up in the country particularly in the State of Punjab during the period 1995-96 and 1996-97;

(b) the production capacity of these mills in the State; and

(c) the expenditure incurred on the setting up of these mills in the State?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) The number of spinning mills set up in Punjab and on all India basis during the year 1995-96 and 1996-97 is given below:

Year	No. of Spinning Mills	
	Punjab	All India
1995-96	2	85
1996-97 upto 31-12-1996	3	17

(b) The installed capacity of 5 spinning mills set up in Punjab during the years 1995-96 and 1996-97 is 43240 spindles and 960 rotors.

(c) The data is not maintained centrally.

देश में बंद पड़ी कपड़ा मिलें

1920. **श्री रामजीलाल:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में बंद पड़ी कपड़ा मिलों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बंद पड़ी मिलों के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा): (क) विगत दो वर्षों (अर्थात् जनवरी, 95 तथा दिसंबर, 96 तक की अवधि के लिए) के दौरान बंद 133 सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें थीं। विभिन्न राज्यों में बंद मिलों की संख्या निम्नानुसार है:—

	राज्य	बंद मिलों की संख्या
1.	आंध्रप्रदेश	10
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	गुजरात	48
5.	हरियाणा	2
6.	कर्नाटक	8
7.	केरल	1
8.	मध्यप्रदेश	8
9.	महाराष्ट्र	15
10.	राजस्थान	4
11.	तमिलनाडु	16
12.	उत्तर प्रदेश	13
13.	पं० बंगाल	5
14.	उड़ीसा	1
	कुल	133

(ख) वस्त्र मिलों की रुग्णता बंद होने के मुख्य कारण ढांचागत रूपांतरण अत्यधिक क्षमता, श्रमिक तथा मशीनों की निम्न उत्पादकता, पुरानी तथा अप्रचलित मशीनरी, आधुनिकीकरण का अभाव तथा अन्य वित्तीय समस्याएं हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने विगत में देश में बंद रुग्ण वस्त्र मिलों को पुनर्जीवित करने हेतु कुछ कदम उठाए हैं। ये निम्नानुसार हैं:

(i) जून, 1985 की वस्त्र नीति के अनुसरण में कमजोर लेकिन अर्थक्षम मिलों के लिए पुनर्वासन पैकेजों को तैयार करने के लिए एक नोडिए अभिकरण गठित किया गया था।

(ii) जून, 1985 की वस्त्र नीति के अनुसार, वस्त्र उद्योग की आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 750/-करोड़ रु० के संग्रह राशि से एक वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना(टी एम एफ एस) का सृजन किया गया ताकि इसकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

(iii) भारत सरकार ने रुग्ण तथा संभवतः रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने की व्यवस्था करने तथा विशेषज्ञों (बी आई एफ आर) के बोर्ड द्वारा, निरोधक, सुधारक, प्रतिकारी तथा अन्य उपायों जिन्हें ऐसी